(b) The suspension was revoked in January, 1991 and the officer was posted to Madras unit with the same powers in keeping with general guidelines in the matter.

(c) The Inquiry was completed in March, 1992 and a major penalty of reduction in pay by one stage for a period of two years was imposed on charged officer by the Competent Authority. He was also transferred from working unit of Madras to the Corporate Office, Delhi.

Payment made by NPCC to M/s. Poriole Experts and Associates

2185. SHRI M. A. BABY : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Deputy General Manager of NPCC posted at Hyderabad made payment of Rs. 5,00,000 to M/s. Poriole Experts and Associates against the Bank Guarantee ignoring the mandatory verifications with Bank before making payments against its guarantee;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether N. P. C. C. has initiated any departmental action against the errant Deputy General Manager and if not, why ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) The Deputy General Manager of NPCC posted at Hyderabad made a payment of Rs. 5 lakhs to M/s. Poriole Experts and Associates after receiving confirmation by post from the Bankers about the issue of the Bank Guarantee. However, subsequently at the time of revalidation of the bank guarantee, the Bankers informed that they had not issued the said bank guarantee and the letter confirming the same. The first information report has been lodged with the police by the Deputy General Manager.

मध्य प्रदेश में बाढ़ से नुकसान

2186. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटुभाई पटेल :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों से भारी नुकसान होता है और इनके कारण इस राज्य के निवासियों को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं तैयार की हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पो. के. थुंगन) : (क) मध्य प्रदेश में बाढ़ के कारण सालाना औसतन क्षति लगभग 4.80 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में यमुना, टोंस तथा सोन नामक तीन नदी प्रणालियों के बाढ़ प्रबंध के वास्ते व्यापक योजनाएं गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा तैयार की गई हैं। इनमें अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक संरचनात्मक उपाय जैसे तटबंध, जलाशय, शहरों की सुरक्षा तथा कटाव-रोधी कार्य और गैर-संरचनात्मक उपाय जैसे बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ मैदान जोनिंग तथा बाढ़ प्रूफिंग शामिल हैं।